आईआईएमए और आईडीडीआरआई द्वारा गुजरात के लिए टिकाऊ डीकार्बोनाइजेशन मार्ग विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला

~ गुजरात सरकार के उद्योग एवं खान, जलवायु परिवर्तन, वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा समर्थित कार्यशाला

~ फ्रांस, इंडोनेशिया, मैक्सिको और ऑस्ट्रेलिया के अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने गुजरात की वर्तमान स्थिति और एनडीसी लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में प्रगति को प्रभावित करने वाले विभिन्न पहलुओं पर सत्र की अध्यक्षता की।

01 नवंबर, 2023: भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद (आईआईएमए) और आईडीडीआरआई ने आज उद्योग एवं खान विभाग, जलवायु परिवर्तन विभाग और वन एवं पर्यावरण विभाग, गुजरात सरकार के सहयोग से 'गुजरात के लिए टिकाऊ डीकार्बोनाइजेशन मार्ग' पर एक दिवसीय हितधारक सहभागिता कार्यशाला का आयोजन किया।

राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) लक्ष्यों को पूरा करने में गुजरात की आगे की राह पर अपने दृष्टिकोण और अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए इस कार्यशाला में फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको और इंडोनेशिया जैसे जी20 सदस्य देशों के अंतर्राष्ट्रीय जलवायु विशेषज्ञों के साथ-साथ राज्य सरकार, उद्योग और शिक्षा जगत के शीर्ष अधिकारियों सहित हितधारकों का एक विविध समूह एक साथ आगे आया।

आईडीडीआरआई से सुश्री मार्ता तोर्रेस गनफॉस; सुश्री मेग अर्गिरिउ जो एक स्वतंत्र रणनीतिक सलाहकार हैं; तेम्पस एनालितिका के डॉ. डैनियल बुइरा और बोगोर कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रिज़ाली बोअर ने क्रमशः जी20 सदस्य देशों फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको और इंडोनेशिया के प्रतिनिधियों के रूप में इस कार्यक्रम में भाग लिया।

ये अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ आगामी कॉप28 में सक्रिय रूप से शामिल हैं जो इस साल के अंत में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा और ये अपनी सरकारों के साथ मिलकर काम करेंगे और उनके नेटवर्क हैं जो मुख्य रूप से वैश्विक दक्षिण के देशों को कवर करते हैं। वे एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क में एक साथ काम करते हैं, मुख्य रूप से वैश्विक दक्षिण के देशों में। उनकी भागीदारी वैश्विक उत्तर का वैश्विक दक्षिण के साथ एक समामेलन है।

इस कार्यशाला का आयोजन वर्तमान रुझानों पर चर्चा को सुविधाजनक बनाने और गुजरात के लिए भारत सरकार की नेट ज़ीरो और एनडीसी प्रतिबद्धताओं से उभरने वाले निहितार्थों और अवसरों की समझ को बढ़ाने के लिए प्रमुख हितधारकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया था। इस आयोजन का उद्देश्य निम्नलिखित विषयों पर नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं और शोधकर्ताओं के बीच खुले और सार्थक विचार-विमर्श को बढ़ावा देना भी है:

- एनडीसी लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में गुजरात की स्थिति और प्रगति
- भारत सरकार की नेट ज़ीरो प्रतिबद्धताओं से उभर रहे गुजरात के लिए निहितार्थ और अवसर
- गुजरात को निम्न-कार्बन और लचीली अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए प्रमुख नीतिगत हस्तक्षेप और कार्रवाइयों की आवश्यकता
- गुजरात की नेट ज़ीरो और एनडीसी यात्रा का समर्थन करने में हितधारकों की भूमिका

उद्घाटन सत्र का नेतृत्व आईआईएमए संकाय सदस्य, प्रोफेसर अमित गर्ग और सुश्री मार्ता तोर्रेस गनफॉस, आईडीडीआरआई पेरिस ने किया, जिन्होंने दिन के दौरान होने वाली चर्चाओं के लिए गुजरात और वैश्विक संदर्भ निर्धारित किया।

कार्यक्रम की रूपरेखा तय करते हुए, **प्रोफेसर अमित गर्ग ने कहा**, "गुजरात अक्षय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, टिकाऊ भवन स्थान, ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और हरित हाइड्रोजन के लिए नीतियों को शुरू करने और लागू करने में सबसे आगे है। हालाँकि, गहरे डीकार्बोनाइजेशन और नेट ज़ीरो 2070 की ओर राज्य के परिवर्तन के लिए कम लागत वाले वित्तपोषण और अंतर्राष्ट्रीय निवेश की आवश्यकता है।"

सुश्री मार्ता तोर्रेस गनफॉस ने कहा, "पेरिस समझौते के जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने से हमारी अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा मिल सकता है और नई नौकरियाँ पैदा हो सकती हैं। हालाँकि, इन अवसरों को भुनाने के लिए, देशों, राज्यों, शहरों और कंपनियों को डिजाइन और योजना चरणों में जलवायु लक्ष्यों पर विचार करना चाहिए - निवेशक, बैंक और बीमाकर्ता कम कार्बन वाले, जलवायु-लचीले भावि युग परिवर्तन के लिए विश्वसनीय और सुसंगत योजनाओं की मांग कर रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर गुजरात अपनी तरह की पहली राज्य-स्तरीय शुद्ध शून्य दीर्घकालिक रणनीति को मूर्त रूप देता है तो उसे प्रतिस्पर्धात्मक लाभ होगा।"

गुजरात महत्वपूर्ण जलवायु परिवर्तन प्रभावों का अनुभव कर रहा है जैसे कि तापमान में वृद्धि, समुद्र के स्तर में वृद्धि, वर्षा के पैटर्न में बदलाव, आदि। तापमान में वृद्धि से गर्मी की लहरें बढ़ती हैं और कृषि उपज प्रभावित होती है, जबकि परिवर्तित मानसून पैटर्न पानी की उपलब्धता को बाधित कर सकता है और महत्वपूर्ण रूप से फसल की पैदावार पर असर कर सकता है। गुजरात में 1600 किमी लंबा तटीय क्षेत्र है जो समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण बाढ़ और तटीय कटाव के खतरे के प्रति संवेदनशील है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित इन प्रभावों के लिए विभिन्न स्थायी उपायों की दिशा में काम करने की आवश्यकता है जैसे कि स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में तेजी लाना, क्षेत्र को कम करने के लिए स्थायी डीकार्बोनाइजेशन मार्गों को सक्षम करना, लाइफ़ मिशन और चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए उचित अनुकूलन उपाय करना और निम्न-कार्बन ऊर्जा परिवर्तन के लिए जलवायु वित्त।

भारत का एक अग्रणी औद्योगिक राज्य होने के नाते, गुजरात को एनडीसी के साथ-साथ भारत द्वारा निर्धारित नेट ज़ीरो लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सराहनीय योगदान देना चाहिए और इन प्रतिबद्धताओं को ठोस आर्थिक अवसरों में बदल सकता है। इसके लिए विभिन्न नीतियों को संरेखित करने और संतुलित करने की आवश्यकता होगी जैसे कि जलवायु परिवर्तन शमन, अनुकूलन और लचीलेपन की ओर ले जाने वाली नीतियां, स्वच्छ ऊर्जा नीतियों को बढ़ावा देना, ऐसी नीतियाँ जो ऊर्जा प्रणाली के परिवर्तन की ओर ले जाती हैं, कठिन क्षेत्रों का डीकार्बोनाइजेशन, ऐसी नीतियाँ विकसित करना जो चक्रीय अर्थव्यवस्था के लिए नेतृत्व करती हैं, ऐसी नीतियाँ सुनिश्चित करना कि इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप सामाजिक रूप से मजबूत बदलाव हों, अल्पावधि (2030 तक), मध्यम अवधि (2031-2047), और दीर्घकालिक (2048-2070) में LiFE मिशन की ओर बदलाव के लिए जागरूकता पैदा हो। इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप सामाजिक रूप से मजबूत परिवर्तन हों, अल्पावधि (2030 तक), मध्यम अवधि (2031-2047) और दीर्घकालिक (2048-2070) और लाइफ़ मिशन की ओर बदलाव के लिए जागरूकता पैदा करना आदि।

उद्घाटन समारोह के बाद सत्रों की एक श्रृंखला आयोजित की गई, जिसमें अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों ने स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में तेजी लाने, डीकार्बोनाइजेशन में शामिल तकनीकी और वित्तीय

चुनौतियों, प्रभाव, भेद्यता, अनुकूलन और जलवायु लचीलेपन के अवसरों का आकलन करने पर सत्रों की अध्यक्षता की।